आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 27.03.2026
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटाया। राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। रैपिड रेल सेवा का विस्तार हरिद्वार और ऋषिकेश तक करने का अनुरोध किया।
- पिथौरागढ़ में आयोजित पूर्व सैनिक रैली में शामिल हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की पूर्व सैनिकों से अपील की।
- पौड़ी जिले में एलपीजी की सुचारू आपूर्ति के लिए प्रशासन ने सख्त की निगरानी। विभिन्न क्षेत्रों में 53 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण।

पेट्रोल–डीजल/शुल्क

सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दस रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह निर्णय पश्चिम एशिया संकट के बीच लिया गया है। उन्होंने कहा कि डीजल के निर्यात पर 21 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर 29 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर शुल्क लगाया गया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है।

इसके अलावा सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसमें से 20 प्रतिशत आवंटन इस्पात, ऑटोमोबिल, कपड़ा और अन्य श्रम प्रधान उद्योगों को दिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसका उद्देश्य वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को सुगम बनाना है।

मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में केंद्र के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को उत्तराखण्ड में संचालित विशिष्ट पहलों और प्रमुख सुधारों की भी विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से मेरठ तक संचालित रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम– आर.आर.टी.एस परियोजना का विस्तार मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक किए जाने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। साथ ही उत्तराखण्ड में रक्षा उपकरण निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए नीति समर्थन और प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया। उन्होंने राज्य की सामरिक स्थिति, उपलब्ध प्रशिक्षित मानव संसाधन और विकसित औद्योगिक ढांचे को इस

दिशा में उपयुक्त बताया। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार, हरिद्वार और देहरादून में रक्षा उपकरण उत्पादन औद्योगिक केंद्र की स्थापना पर भी केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। श्री धामी ने रायवाला क्षेत्र में बीआई–डक ब्रिज के विकास और उत्तरकाशी जिले में स्थित चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने टिहरी झील में सी–प्लेन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने दिल्ली–हल्द्वानी एक्सप्रेस–वे के निर्माण का अनुरोध भी किया।

रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत ऋषिकेश से व्यासी खंड के शीघ्र लोकार्पण, टनकपुर–बागेश्वर रेल लाइन में रोड–कम–रेल टनल निर्माण, बागेश्वर–कर्णप्रयाग नई रेल लाइन के सर्वे और हरिद्वार–देहरादून रेल लाइन के डबलिंग का अनुरोध किया। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरकाशी क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए ऋषिकेश–उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखण्ड आगमन का निमंत्रण देते हुए विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का प्रस्ताव भी रखा। प्रस्तावित लोकार्पण में दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस–वे और टिहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट शामिल हैं, जबकि शिलान्यास के लिए पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना शामिल हैं।

आपदा प्रबंधन समिति बैठक

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति की बैठक हुई। बैठक में आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्य से संभावित संवेदनशील क्षेत्रों में प्रस्तावित सुरक्षात्मक कार्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के तहत अनुमोदित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा न्यूनीकरण से जुड़े कार्य सुधारात्मक प्रकृति के होते हैं, जिन्हें जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि तहसील स्तर और विभिन्न विभागों से प्राप्त नदियों के चैनलाइजेशन और ड्रैजिंग से संबंधित प्रस्तावों को समिति ने स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही विभागों को निर्देशित किया गया कि जनहित से जुड़े सभी आपदा न्यूनीकरण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अगर विभागों के पास अतिरिक्त प्रस्ताव या सुझाव हों, तो उन्हें शीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

पूर्व सैनिक रैली

पिथौरागढ़ छावनी क्षेत्र में आज 12 कुमाऊँ रेजीमेंट की ओर से मेगा पूर्व सैनिक रैली आयोजित की गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने ज़ोरावर साइकिल रैली का झंडी दिखाकर समापन किया और प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने पूर्व सैनिकों और और वीर नारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिक देश की अमूल्य धरोहर हैं और उनके अनुभव समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका

निभा सकते हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने और जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देने की अपील भी की। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों को होम–स्टे संचालित करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सैनिक परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाने का सुझाव दिया।

इससे पहले राज्यपाल ने नैनी–सैनी हवाई अड्डा परिसर में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने उत्पादों की पैकेजिंग की सराहना करते हुए महिलाओं की आय में हो रही वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा इसे और बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों और समूहों को प्रोत्साहित किया।

गैस आपूर्ति अभियान

पौड़ी जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति को पारदर्शी और सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने निगरानी तंत्र को और सशक्त कर दिया है। आज प्रशासन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दलों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ सघन निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान 53 प्रतिष्ठानों की जांच की गयी, जिनमें 16 गैस गोदाम, 02 पेट्रोल पम्प और 35 व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान दलों ने स्टॉक रजिस्टर, वितरण प्रणाली और निर्धारित मानकों के अनुपालन की बारीकी से जांच की। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि उपभोक्ताओं को समय पर और निर्धारित मात्रा में गैस उपलब्ध हो रही है या नहीं। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में गैस आपूर्ति व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पाठ्य पुस्तक वितरण

चम्पावत जिले में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आज निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चम्पावत से पुस्तक वाहनों को जिले के विकासखण्डों और न्याय पंचायतों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह ने बताया कि सरकार हर साल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करती है। इसी क्रम में चम्पावत जिले में कुल 647 विद्यालयों में कक्षा एक से 12 तक के छात्र–छात्राओं के लिए पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके तहत दो लाख छियालीस हजार पांच सौ छह पुस्तकों की आवश्यकता के सापेक्ष अभी 29 हजार पुस्तकों का वाहनों के माध्यम से वितरण किया जा रहा है।